साल तीन - बेहतरीन

जन सेवा के तीन साल
समान विकास हुआ बेमिसाल

मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है ,
जैसा वह विश्वास करता है ,वैसा ही वह बन जाता है

संदेश

मेरे प्रिय हरियाणावासियों,

हमारी सरकार ने जन सेवा के तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं। इस वर्ष हम हरियाणा के गठन के 51 वर्ष पूरे कर चुके हैं और स्वर्ण जयन्ती वर्ष का समापन हर्षोल्लास से कर रहे हैं। यह क्षण प्रत्येक हरियाणावासी के लिए बेहद ही गौरवपूर्ण है। हमारी सरकार ने तीन वर्ष पूर्व जिस उम्मीद से प्रदेश के नव-निर्माण का संकल्प लिया था, आज वह आपके सहयोग और हमारी कल्याणकारी नीतियों से पूर्ण हो रहा है। हमने अपने हरसम्भव प्रयास किये हैं कि इन तीन सालों में प्रदेश को एक बेहतरीन, भ्रष्टाचार -मुक्त और पारदर्शी प्रशासन दे सकें। हमारी कथनी और करनी एक रही है, इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश की सभी 90 विधान सभा क्षेत्रों का बिना भेदभाव के एकसमान विकास करने की एक नई मिसाल पैदा की है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी वर्ग एवं व्यक्ति सरकार की कल्याणकारी नीतियों के लाभ से वंचित न रहे।

मुझे प्रसन्नता है कि इन तीन सालों में हमने सभी प्रकार की चुनौतियों का डटकर सामना किया है, ताकि हरियाणा के भाईचारे और सौहार्द को कोई भी ठेस न पहुंचा सके। इसी प्रकार, हमारी सरकार ने जन हितैषी निर्णय लेते हुए किसानों के कल्याण एवं कृषि क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए कई अहम् फैसले लिए हैं। प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों के लिए उचित मुआवजा दरें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान हितेषी सहकारी नीतियां, फसलों के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि, बागवानी फसलों को बढ़ावा एवं पशुधन के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रभावी प्रयास आज स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय दर्शन' को अपनाया है।

इसी श्रंखला में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने एवं उन्हें सुरक्षित समाज देना हमारी प्राथमिकता रही है। हमने इसी उद्देश्य से हर जिले में महिला पुलिस थाना तथा खण्ड स्तर पर महिला हैल्प डैस्क स्थापित किये हैं, ताकि महिलाएं अपनी शिकायत बेझिझक कर सकें। यही नहीं, हमने मजदूर कल्याण, शिक्षा के प्रसार, आधारभूत संरचना का विकास, शहरों और गांवों के स्मार्ट विकास के कई अहम् कदम उठाये हैं। आज हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश ही नहीं अपितु 'डिजिटल हरियाणा' के रूप में भी जाना जाता है।

हरियाणा के प्रत्येक नागरिक के लिए यह गर्व का विषय है कि आज हरियाणा की गिनती देश के चुनिंदा राज्यों में की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी हरियाणा सरकार की नीतियों की प्रशंसा की है। हरियाणा को अभी और आगे ले जाना है, जिसके लिए हमें पूर्व की भान्ति आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है, ताकि हम इसी तरह मिलकर प्रदेश के विकास रूपी रथ को आगे बढ़ा सकें और 'विकसित हरियाणा' के सपने को साकार रूप दे सकें।

इसी शुभेच्छा के साथ .....

आपका

मनोहर लाल

मुख्यमंत्री, हरियाणा

प्रदेश को मिले कई अवार्ड एवं पुरस्कार

- भूमि के ई-पंजीकरण के लिए ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- जी.आई.एस.टैक्नोलोजी के अनूठे उपयोग के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड।
- भूमि के ई-पंजीकरण के लिए ''स्कॉच आर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड''।
- गोवा में ''इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज अवार्ड'' मिला।
- ई-शासन प्रणाली के बेहतर इस्तेमाल के लिए 'स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस' अवार्ड-2015 मिला।
- जन्म के समय ही आधार पंजीकरण के लिए ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड'' एवं ''फर्स्ट स्टेट आफ इंडिया अवार्ड''।
- ई-टूरिजम सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग हेतु ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- समेकित वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के लिए ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- ई-जिला/ई-दिशा/ सक्षम ई-पेंशन एकीकरण के लिए ''स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड''।
- ई-शासन पहलों के लिए 'एक्सिलेंस ऑफ सीएसआई.नीहिलेंट' अवार्ड।
- तीन जिलों पंचकूला, जींद व सिरसा के लिए ''श्री डिजिटल इण्डिया'' अवार्ड।
- एस.आर.डी.बी. (स्टेट रेजीडेंट डाटा बेस) के लिए ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- केन्द्रित फाइल मूवमेंट एवं ट्रैकिंग सिस्टम हेतु ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- आधार सक्षम बायोमैट्रिक एटेंडेंस सिस्टम हेतु ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- औषध खरीद एवं आपूर्ति श्रंखला प्रबन्धन हेतु ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- संसाधन पर ई-टैक्स कटौती हेतु ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- ई-ग्रास (सरकारी प्राप्तियां स्वीकार प्रणाली) हेतु ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- डीलर्स प्रबन्धन हेतु ई-एप्लीकेशन, रिटर्नस की ई-फाईलिंग, सी-फार्म हेतु ''स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड'' व ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।

प्रदेश को मिले कई अवार्ड एवं पुरस्कार

- जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ई.आर.पी. प्रणाली हेतु ''स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड'' व ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु ''बेस्ट स्टेट सब्सक्राईबर कवरेज-पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण अवार्ड''।
- ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य एवं ''श्रेष्ठ उन्नत राज्य के लिए ई-गवर्नेंस अवार्ड''।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में बेहतरीन योगदान हेतु ''वेब रत्तना स्टेट सिल्वर अवार्ड''।
- कैशलैस लेन-देन की पहल करने के लिए ''डिजिटल इंडिया अवार्ड''।
- ई-स्टैम्पिंग/ई-ग्रास का एकीकरण हेतु ''सीएसआई.निहीलेंट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस''।
- 'थारी पेंशन थारे पास योजना' हेतु ''स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्डस'' व ''स्कॉच ऑर्डर आफ मेरिट अवार्ड''।
- ई.बी.टी.योजना के लिए ''कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्रशंसा पुरस्कार''।
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में यमुनानगर को ''बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ'' अवार्ड।
- चावल उत्पादकता के लिए राज्य को 'कृषि कर्मण' पुरस्कार।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत।
- देश में ऑफ ग्रिड बायोमास बगैर गैस आधारित संयंत्रों की सर्वोच्च अतिरिक्त क्षमता हेतु प्रथम पुरस्कार।
- नवीनीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों की स्थापना हेतु राज्य को तृतीय पुरस्कार।
- जनसंख्या स्थिरीकरण नवजात शिशु एवं मातृ उत्तरजीविता श्रेणियों में पुरस्कार।

मंत्री परिषद्

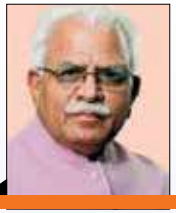

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री
चौथी मंजिल, सचिवालय

राम बिलास शर्मा
शिक्षा मंत्री
कमरा नं. 32/8, सचिवालय

कैप्टन अभिमन्यु
वित्त मंत्री
कमरा नं. 40/5, सचिवालय

ओम प्रकाश धनखड़
कृषि मंत्री
कमरा नं. 34/8, सचिवालय

अनिल विज
स्वास्थ्य मंत्री
कमरा नं. 49/8, सचिवालय

नरबीर सिंह
लोक निर्माण मंत्री
कमरा नं. 39/8, सचिवालय

कविता जैन
सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग मंत्री
कमरा नं. 43-ए/8, सचिवालय

कृष्ण लाल पंवार
परिवहन मंत्री
कमरा नं 24/8, सचिवालय

विपुल गोयल
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री
कमरा नं. 42/6, सचिवालय

राज्य मंत्री

मनीष कुमार ग्रोवर
सहकारिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार
कमरा नं. 43 सी/8, सचिवालय

कृष्ण कुमार बेदी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
कमरा नं. 31/8, सचिवालय

कर्ण देव काम्बोज
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री
कमरा नं. 47/8, सचिवालय

नायब सिंह
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
कमरा नं. 44बी/6, सचिवालय

डॉ. बनवारी लाल
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्य मंत्री
कमरा नं. 29/8, सचिवालय

अनुक्रम

किसान कल्याण	10
बागवानी फसलों से किसानों को अतिरिक्त आय	15
पशुधन संवर्धन एवं संरक्षण के अटूट प्रयास	17
हर खेत को पानी देने के लिए कटिबद्ध	21
उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित	25
हरा-भरा म्हारा हरियाणा	26
ग्रामीण विकास बनी मिसाल	28
हरियाणा के शहर बन रहे स्मार्ट	34
शिक्षा हब बन रहा हरियाणा	36
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	39
जगमग हरियाणा	41
आधुनिकता की मिसाल बनी एक्सप्रैस-वे एवं सड़कें	44
हरियाणा की नई पहचान-मैट्रो, रेल एवं हवाई सेवाएं	46
अंत्योदय दर्शन से गरीबों का कल्याण	48
प्राथमिक ध्येय-सर्वजन हिताय	50
पर्यटकों को लुभाता हरियाणा	54
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण	56
महिलाओं के स्वावलम्बन पर बल	58
श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा	65
वीर एवं शहीदों का बढ़ाया सम्मान	68
हमारा प्रयास सबको आवास	70
कर्मचारियों के कल्याणार्थ योजनाएं	72
उद्योगों का विस्तार	74
विदेशी निवेश को बढ़ावा	78
कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के नए प्रयास	82
सुदृढ़ अर्थव्यवस्था	84
विकास का परिचायक	84
पत्रकारों को अपार सुविधाएं	86
आधुनिक एवं सुगम परिवहन सेवाएं	87
हर जन हो स्वस्थ	89
आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी	93
खेलों में हरियाणा का परचम	94
सुदृढ़ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	100
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन	102
रोजगार से आत्मनिर्भर होते युवा	104
राजस्व बढ़ोतरी की दर सही दिशा में	106
डिजिटल हरियाणा की नई तस्वीर	108

किसान कल्याण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रीमियम दर

- खरीफ फसल-अधिकतम 2 प्रतिशत।
- खरीफ फसलों में धान, बाजरा, मक्का व कपास फसलें शामिल (कपास की फसल पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान राज्य सरकार द्वारा)।
- रबी फसल-अधिकतम 1.5 प्रतिशत।
- रबी फसलों में गेहूं, जौ, सरसों व चना शामिल।
- वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें - अधिकतम 5 प्रतिशत।

अब तक लगभग 260 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित

प्रति हैक्टेयर बीमित राशि निर्धारित

- धान के लिए 71,500 रुपये।
- कपास के लिए 69,000 रुपये।
- बाजरा के लिए 33,500 रुपये।
- मक्का के लिए 36,000 रुपये।
- खड़ी फसल में सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट एवं बीमारी, आसमानी बिजली, तूफान चक्रवात व ओलावृष्टि आदि रिस्क शामिल।

वर्ष 2017-18 में योजना के तहत 300 करोड़ रुपये का प्रावधान

किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुआवजा राशि

मुआवजा दरों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी

- बाढ़, जलभराव, अग्नि, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान एवं सफेद मक्खी का प्रकोप प्राकृतिक आपदा में शामिल।
- खराब फसलों के लिए मार्च, 2015 से 12,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा।
- कम से कम नुकसान होने पर छोटे से छोटे हिस्सेदार को भी न्यूनतम 500 रुपये मुआवजा।

अब तक किसानों को 2476.59 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित
(वर्ष 2013-14 की बकाया 268.74 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल)

किसानों को सहकारी ऋण व अन्य राहतें

- फरवरी-मार्च, 2015 में जिन किसानों की 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसलों के नुकसान हुए, उनके फसली ऋणों को 3 वर्ष के लिए मध्यम अवधि ऋणों में बदला।
- किसानों को 32,074 करोड़ रुपये के फसली ऋण दिए।
- समय पर अदायगी करने वाले किसानों को सहकारी ऋण ब्याज रहित।
- जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अधिक फसलें खराब हुई उनमें एक वर्ष के लिए किसानों के कृषि के बिल शत-प्रतिशत माफ।
- जिन क्षेत्रों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक फसलें खराब हुई, उनमें किसानों के टयूबवैल के बिल 50 प्रतिशत माफ।

राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल

E-NAM Portal

- प्रथम चरण में 54 अनाज मण्डियों को जोड़ा।
- द्वितीय चरण में शेष 54 अनाज मण्डियों को मार्च, 2018 तक जोड़ने का लक्ष्य।
- फरूखनगर, गुरुग्राम एवं पंचकूला सेब मार्किट को प्लेटफार्म से जोड़ने का कार्य प्रस्तावित।

कृषक उपहार योजना

- मण्डियों में 5000 रुपये या इससे अधिक की सरसों, कपास, बासमती, ग्वार व मक्का जैसी फसलें लाने वाले किसानों को प्रोत्साहन।
- किसानों को 12 करोड़ रुपये के ईनाम, जिनमें ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, कल्टीवेटर व दीवार घड़ी जैसे उपहार दिये जाते हैं।

गन्ने का भाव देश में सर्वाधिक

- अगेती किस्म-310 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये प्रति क्विंटल।
- मध्यम किस्म-305 रुपये से बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल।
- पछेती किस्म -300 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपये प्रति क्विंटल।

- पिराई सत्र 2016-17 के दौरान सभी सहकारी चीनी मिलों द्वारा कुल 3.62 करोड़ क्विंटल गन्ने की पिराई की गई, जोकि हरियाणा के इतिहास में सर्वाधिक है।

बागवानी फसलों से किसानों को अतिरिक्त आय

बागवानी विज़न-2030

» आगामी 15 वर्षों में बागवानी क्षेत्र को दोगुना व उत्पादन को तिगुणा करने का लक्ष्य।

» बागवानी के अन्तर्गत कुल खेती क्षेत्र 7.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना।

फसल विविधिकरण

» औषधीय पौधों, फलों, सब्जियों व फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान राशि।

बागवानी उत्कृष्टता केन्द्र

» प्रदेश के प्रत्येक जिले में खोले जा रहे हैं।

» होडल (पलवल) एवं सुन्द्राह (नारनौल) में कार्य प्रगति पर।

फसल कलस्टर विकास कार्यक्रम तैयार

- प्रदेश में 140 फसल कलस्टर एवं 340 बागवानी ग्राम घोषित।
- 510 करोड़ रुपये की लागत से 140 फल एवं सब्जी संग्रह एवं पैक हाउस की स्थापना होगी।
- बागवानी से सम्बन्धित उत्पादों के लिए 'हरियाणा फ्रैश' ब्रांड शुरू।
- गांव अंजनथली (करनाल) में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापनाा की ओर।
- अधिक शोषित एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर किसानों को 85 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाएगी।
- बागवानी क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों के लिए वर्ष, 2016 में "Best Horticulture State Award" मिला।
- एकीकृत उद्यान विकास मिशन के अन्तर्गत बागवानी फसलों एवं गतिविधियों पर 258 करोड़ रुपये खर्च।
- किसानों एवं उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर ताजा फल एवं सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए पंचकूला में 'किसान बाजार' शुरू।

पशुधन संवर्धन एवं संरक्षण के अटूट प्रयास

हरियाणा गौ-वंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम-2015 लागू

- गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास व एक लाख रुपये तक का जुर्माना।
- अवैध गौ तस्करी करने पर सात वर्ष की कैद एवं प्रयुक्त वाहन को जब्त करके अतिरिक्त 70 हजार रुपये तक का जुर्माना।
- जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक साल तक की अतिरिक्त कैद।

एकीकृत पशुधन बीमा योजना

- देसी/संकर नस्ल के दुधारू पशु, बकरी, भेड़, शूकर, घोड़े, गधे, खच्चर व ऊंट इत्यादि का बीमा।
- पशुपालकों को 5 बड़े तथा 50 छोटे पशुओं तक के बीमा हेतु प्रीमियम पर अनुदान।
- बड़े पशु के मात्र 100 रुपये तथा छोटे पशु के लिए मात्र 25 रुपये तीन वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रीमियम की राशि अदा करनी है।
- अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए यह सुविधा निःशुल्क।

देसी गायों की मिनी डेरी योजना

- देसी नस्ल की 3 व 5 गायों की डेरी इकाई लगाने पर 50 प्रतिशन अनुदान।
- हरयाना नस्ल की 3 व 5 गायों की लघु डेरी इकाई की स्थापना पर क्रमशः 75 हजार रुपये व 1.25 लाख रुपये तक की अनुदान राशि।
- साहीवाल नस्ल की 3 व 5 गायों की लघु डेरी इकाई की स्थापना पर क्रमशः 1,12,500 रुपये व 1,87,500 रुपये तक की अनुदान राशि।

हरियाणा देश का पहला राज्य जहां देसी गाय पास्चुरीकृत 'ए-2' दूध वीटा बूथों पर उपलब्ध

- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 878 ग्राम दूध उपलब्धता के साथ हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह मात्र 329 ग्राम है।
- पशु स्वास्थ्य जांच सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर पर मोबाईल पशु चिकित्सा एवं रोग निदान प्रयोगशालाएं शुरू।

पशुओं के लिए गौ अभ्यारण्य

- देसी गायों की नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना जल्द।
- हिसार तथा पानीपत जिलों में गौ अभ्यारण्यों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू।
- इण्डो इजराईल उत्कृष्टता केन्द्र हिसार में स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

- सहकारी दुग्ध उत्पादकों की अनुदान राशि 4 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर की।
- वर्ष 2017-18 में 25.90 करोड़ रुपये की राशि वितरित।

पशुपालकों को अन्य प्रोत्साहन

- हरयाना व साहीवाल नस्ल की अधिक दूध देने वाली गाय के मालिकों को 10 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि।
- अधिक दूध देने वाली मुर्राह भैंस के मालिकों को 10 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि।
- दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को बेटी की शादी पर 1100 रुपये कन्यादान राशि।
- समिति के सदस्यों के 10वीं एवं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को 80 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने पर क्रमशः 2100 रुपये व 5100 रुपये की छात्रवृत्ति राशि।
- प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्यों के लिए 5 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना शुरू।

हर खेत को पानी देने के लिए कटिबद्ध

दशकों बाद पहुंचाया पानी

- 39 वर्षों बाद हसनपुर एवं दनचौली माइनरों में पहली बार पानी।
- 39 वर्षों बाद माधोगढ़ व सुरहेति माइनरों (नारनौल-रेवाड़ी क्षेत्र)।
- 30 वर्षों बाद निंबहेड़ा माइनर (लोहारू क्षेत्र) में।
- 24 वर्षों बाद दिवाना माइनर (नारनौल-रेवाड़ी क्षेत्र) में।
- 20 वर्षों बाद लाडावास, दमकोरा व डागरोली माइनरों (लोहारू क्षेत्र) में।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- देश की पहली योजना, जिसमें सौर ऊर्जा व ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा का आदान-प्रदान होगा।
- देश की पहली सूक्ष्म सिंचाई योजना के पायलट प्रोजेक्ट का गुमथला गड्डू (कुरुक्षेत्र) में उद्घाटन।
- 13 जिलों के 36 खण्ड, जोकि डार्क जोन घोषित किए गये हैं, को शामिल किया।

सतलुज-यमुना लिंक नहर बनाने का कृत संकल्प

- हरियाणा सरकार रावी-ब्यास नदियों से राज्य का वैध हिस्से का पानी लेने के लिए कटिबद्ध।
- 28.11.2016 को महामहिम राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन सौंपा।
- 22.4.2017 को माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को नहर का कार्य जल्द शुरू करवाने के लिए पत्र लिखा।

नहरों की मरम्मत और सफाई

- 564 जलमार्गों की एक परियोजना के लिए नाबार्ड से 300 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- 110 जलमार्गों का कार्य पूर्ण, 140 जलमार्गों का कार्य प्रगति पर।

हर खेत को पानी देने के लिए कटिबद्ध

- सिरसा के नाईवाला खरीफ चैनल का निर्माण कार्य जल्द होगा पूरा।
- कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर को ताजा पानी उपलब्ध करवाने की योजना जल्द होगी पूरी।
- ''हर खेत को पानी'' उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पम्पों और 143 करोड़ रुपये की जेएलएन. नहर प्रणाली की क्षमता बढ़ाने की एक परियोजना स्वीकृत।
- टेल तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों की मरम्मत और सफाई पर 225 करोड़ रुपये खर्च, वर्ष 2017-18 में करीब 20 चैनलों के पुनः निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी की 451.56 करोड़ रुपये लागत की 327 नई योजनाएं स्वीकृत।
- बाढ़ के पानी से सिंचाई और भू-जल संरक्षण के लिए 390 इंजेक्शन कुएं लगाने का कार्य प्रगति पर।
- मेवात क्षेत्र में भू-जल संरक्षण, पीने के पानी व सिंचाई के लिए कोटला झील का लगभग 81 करोड़ रुपये की लागत से पुनरोद्धार एवं विकास का कार्य जल्द पूरा होगा ।

उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित

पहली अप्रैल, 2017 से कैरोसिन मुक्त हुआ हरियाणा

- वर्ष 2015-16 में बाजरे व सूरजमुखी की, वर्ष 2016-17 में मूंग की तथा वर्ष 2017-18 में सरसों की पहली बार सरकारी खरीद बड़े पैमाने पर।
- खाद्यान्नों की ई-खरीद व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू।
- ईपीडीएस.पोर्टल शुरू, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता।
- 9500 दुकानों पर स्वचालन/बिक्री के उपकरणों (पीओ.एस.) के द्वारा 1.36 करोड़ उपभोक्ताओं को राशन।

हरा-भरा म्हारा हरियाणा

हर घर हरियाली

- हर घर को हरा-भरा बनाने के लिए 12 लाख कलमी पौधे रोपित करने प्रस्तावित।
- चालू वित्त वर्ष में 2.46 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य।
- देशज प्रजातियों के रोपण पर जोर।

अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल वन

- मोरनी क्षेत्र में 17 हजार एकड़ क्षेत्रफल में विश्व हर्बल वन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू।
- पतंजलि अनुसंधान संस्थान दिव्य योग मंदिर, हरिद्वार के सहयोग से हो रहा स्थापित।
- मौजूदा वित्त वर्ष में 400 एकड़ क्षेत्रफल में औषधीय पौधे रोपित।

पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरुकता

- 2200 स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- 2487 ग्राम वन समितियों का गठन।
- 25 हजार ग्रामीण महिलाओं का आजीविका कमाने हेतु सशक्तिकरण।
- प्रत्येक शहर के साथ-साथ सड़कों के सौंदर्यकरण के लिए 110 कि.मी. पर पौधारोपण।
- रेलवे भूमि पर पौधारोपण करने हेतु रेलवे प्रशासन के साथ समझौता।

और जल्द ही विभिन्न जिलों में सिटी फॉरेस्ट होंगे विकसित

वन्य प्राणियों का संरक्षण

- चीतों (Panthers) की संख्या जांचने हेतु कैमरा ट्रैप सिस्टम लागू।
- कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में इस सिस्टम के तहत 23 चीते पाये गये।

ग्रामीण विकास बनी मिसाल

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- वर्ष 2019 तक पूर्णतया स्वच्छ बनाने का लक्ष्य।
- सभी ग्रामीण क्षेत्र हुए खुले में शौच मुक्त।
- 6205 गांवों में बने 28,82,916 व्यक्तिगत शौचालय।

दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना

- 3,000-5,000 तक की आबादी वाले 1700 गांवों के विकास पर 5 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च।
- चालू वित्त वर्ष में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान।

स्वर्ण जयन्ती स्वच्छता पुरस्कार योजना

- खण्ड व जिला स्तर पर एक सबसे साफ-सुथरी, हरी-भरी व खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत को पुरस्कार।
- हर माह एक-एक लाख रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप।
- जिले में सार्वजनिक शौचालय के बेहतर रख-रखाव के लिए भी 10,000 रुपये का पुरस्कार।

आई.टी. युक्त ग्राम सचिवालय

- वर्ष 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय प्रस्तावित।
- सभी विभागों के ग्राम स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी एक ही परिसर में होंगे उपलब्ध।
- पंचायतों से सीधे सम्पर्क बनाने के लिए ई-पंचायत संवाद कार्यक्रम का रोहतक से शुभारम्भ।
- अगस्त, 2017 तक 1579 ग्राम सचिवालय स्थापित।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

- प्रथम चरण में प्रदेश के सभी सांसदों ने 15 गांव गोद लिये।
- आदर्श ग्राम के रूप में अब तक 592 विकास कार्य पूरे तथा 158 कार्यों पर विकास जारी।
- दूसरे चरण में प्रदेश के 9 सांसदों ने 9 गांव गोद लिये।

विधायक आदर्श ग्राम योजना

- प्रथम चरण में 65 विधायकों ने 65 गांव गोद लिये तथा दूसरे चरण में 6 गांवों का चयन किया।
- अब तक 44 चयनित गांवों को 36.20 करोड़ रुपये की राशि जारी।

ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता

- सोशल ऑडिट की अवधारणा को अपनाया।
- गांव के ही लगभग 10 लोगों की कमेटी बनाकर विकास कार्य सुनिश्चित करवाना।
- 20 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों का थर्ड पार्टी द्वारा निरीक्षण।
- सितम्बर, 2017 तक ग्राम पंचायतों को 2787.76 करोड़ रुपये की राशि जारी।

हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

- आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य।
- गत वर्ष 279.13 करोड़ रुपये की राशि जारी।
- चालू वित्त वर्ष के लिए 320 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित।

स्वर्ण जयन्ती महाग्राम विकास योजना

- 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव योजना में शामिल।
- वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक योजना लागू।
- बड़े गांवों को व्यापार, विपणन सुविधा, सामाजिक एवं ढांचागत विकास, शिक्षण संस्थान एवं मानव विकास के तौर पर विकसित करना।

साक्षर एवं सशक्त पंचायतें बनी मिसाल

- निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शिक्षा निर्धारित।
- आपराधिक प्रवृत्ति वाले, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, बिजली बिल व सहकारी संस्थानों के बकाया का नियमित भुगतान न करने वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी।
- नतीजन पहली बार पढ़े-लिखे, बेदाग एवं साफ छवि वाले, युवाओं एवं महिलाओं का चयन हुआ।

अन्य सुविधाएं

- गांवों में ग्राम गौरव पट्ट लगाने का कार्य शुरू, 10 गांवों में कार्य पूर्ण तथा 871 गांवों में कार्य प्रगति पर।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पलवल एवं फरीदाबाद जिलों के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 12 गांवों को 21 लाख रुपये प्रति गांव दिये।
- माननीय राष्ट्रपति द्वारा गोद लिये गुरुग्राम जिले के गांव अलीपुर, दौलह, हरचन्दपुर, ताजनगर तथा रोजकामेव (मेवात) को स्मार्ट गांव बनाया जा रहा है।

जनप्रतिनिधियों के मानदेय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी

मानदेय

- जिला परिषद अध्यक्ष- 7500 से 10,000 रुपये।
  उपाध्यक्ष - 6000 से 75,00 रुपये।
  सदस्य-2500 से 3000 रुपये।
- पंचायत समिति अध्यक्ष- 6000 रुपये से 7500 रुपये।
  उपाध्यक्ष- 2500 रुपये से 3500 रुपये।
  सदस्य -1250 रुपये से 1600 रुपये।
- सरपंच- 2000 रुपये से 3000 रुपये।
- पंच- 600 रुपये से 1000 रुपये।
- गांवों में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 1 नवम्बर, 2016 से 8100 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक।

हरियाणा के शहर बन रहे स्मार्ट

अटल मिशन योजना (अमृत)

- हर घर को पानी की सप्लाई, सीवरेज कनैक्शन।
- प्रदूषण कम करने एवं पार्कों को हरा-भरा बनाने के लिए 18 शहरी स्थानीय निकाय शामिल।
- 2565.74 करोड़ रुपये योजना के तहत आवंटित।

स्मार्ट सिटी

- राष्ट्रीय परियोजना के तहत फरीदाबाद व करनाल शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित।
- इन शहरों में अत्याधुनिक सुविधाओं का होगा विकास।
- गुरुग्राम को राज्य सरकार अपने संसाधनों से बनायेगी स्मार्ट सिटी।
- जींद एन.सी.आर. में शामिल।

शहरी विकास

- नगर निकायों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 8730.92 करोड़ रुपये दिये।
- राजीव गांधी शहरी विकास मिशन के तहत 2690.07 करोड़ रुपये नगरपालिकाओं को दिये।
- हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में उत्पन्न अपशिष्ट के लिए ठोस कचरा प्रबन्धन संयंत्र लगाने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. का लाभ देने का प्रावधान।
- स्वच्छता सर्वेक्षण-2017 में करनाल शहर उत्तरी भारत में 2 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में पहले स्थान पर चुना गया।
- ट्रांजिट ऑरिएंटिड नीति के तहत जनसंख्या की सघनता को ध्यान में रखते हुए मैट्रो मार्गों के साथ-साथ उन्नत बुनियादी ढांचा विकसित होगा।
- बिल्डरों व डैवलपर की मनमानी से ग्राहकों को राहत दिलाने के लिए हरियाणा रियल एस्टेट अधिनियम (रेरा) लागू।

शहरों में स्वच्छता अभियान

- 80 शहरी स्थानीय निकाय हुए खुले से शौच मुक्त।
- 41,200 व्यक्तिगत, 436 सामुदायिक, 552 सार्वजनिक तथा 561 मोबाईल शौचालय बनाए।
- व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु 14,000 रुपये।
- शहरी स्वच्छता पुरस्कार योजना के तहत नगर-निगम को 2 लाख रुपये, नगर परिषद को एक लाख रुपये तथा नगरपालिका के सबसे अच्छे वार्ड को 50,000 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप।

शिक्षा हब बन रहा हरियाणा

नये महाविद्यालयों की स्थापना

- 8 नये राजकीय महाविद्यालय खोले।
- भूना (फतेहाबाद), खेड़ी गुरान (फरीदाबाद), अटेली (महेन्द्रगढ़), सिरसा, अलेवा (जीन्द), बरोटा (सोनीपत), हथीन (पलवल) व महिला महाविद्यालय पुन्हाना (मेवात)।
- 18 राजकीय महाविद्यालयों के नये भवनों व तीन अतिरिक्त भवनों का शिलान्यास।

नई शिक्षा नीति

- शिक्षा शास्त्रियों, अध्यापकों, बुद्धिजीवियों, गैर सरकारी संगठनों, विद्यार्थियों एवं आम जनता से प्राप्त सुझावों एवं गहन मंथन से बनाई जा रही है नई शिक्षा नीति।
- 6072 ग्राम पंचायतों, 126 खण्डों, 78 शहरी स्थानीय निकायों एवं 21 जिलों से सुझाव प्राप्त हुए।
- गीता के श्लोक, स्वच्छता अभियान, योगा व सड़क सुरक्षा स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल।

स्कूलों में ढांचागत सुधार

- पहली से बारहवीं कक्षा तक की मासिक परीक्षाएं आयोजित।
- दिसम्बर, 2017 तक सभी स्कूलों में डैस्क उपलब्ध करवाने की योजना।
- कक्षा 9वीं से 12वीं तक सैमेस्टर सिस्टम समाप्त।
- स्व-अनुशासन हेतु अध्यापक डायरी की अनिवार्यता।
- अध्यापकों के लिए नई ऑनलाइन स्थानांतरण नीति।
- जे.बी.टी. तथा सी.एण्ड.वी. अध्यापकों के लिए अन्तर्जिला स्थानान्तरण नीति लागू।

स्कूलों में रोज़गारपरक शिक्षा

- 990 राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 14 व्यावसायिक ट्रेड्स शुरू।
- इन विद्यालयों में 81,747 विद्यार्थी मौलिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- लगभग 3200 प्राथमिक स्कूलों में रैमेडियल टीचिंग।
- 'मेक इन हरियाणा-मेक इन इण्डिया' अभियान के लिए व्यावसायिक शिक्षा शुरू।

शिक्षा के प्रसार पर जोर

- 35 स्व-वित्त पोषित डिग्री कॉलेज तथा 5 वित्त पोषित विधि (Law) कॉलेज हेतु प्रक्रिया शुरू।
- 9 Self Finance Degree Colleges को 20 नए कोर्स, 4 सीटें बढ़ाने तथा 29 अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 69 नये कोर्स तथा 5 सीटें बढ़ाने तथा वर्ष 2017-18 के लिए 63 नये कोर्स और 4 सीटें बढ़ाने का निर्णय।
- डॉ. मंगलसेन जी के बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध करने तथा उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में एक पीठ स्थापित करने का निर्णय।
- दसवीं कक्षा में 95 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 500 प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

तकनीकी संस्थान

- कुरुक्षेत्र में उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान।
- दुधोला (पलवल) में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय शुरू।
- सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान।
- कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (NIELIT)।
- करनाल में केन्द्रीय प्लास्टिक सैटेलाईट केन्द्र।
- पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (NIFT)।
- 7 नये बहुतकनीकी संस्थानों की स्वीकृति।
- 13 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू।

हरियाणा कौशल विकास मिशन

- हरियाणा कौशल विकास मिशन गठित ।
- ''सूर्य''- युवाओं की स्किलिंग, अप स्किलिंग/ रि-स्किलिंग/असैस्मैंट।
- 'दक्ष'- अन्य विभागों की कौशल पहलों के तहत युवाओं का कौशल प्रशिक्षण।

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

- एकीकृत कौशल विकास योजना क्रियान्वित।
- 7626 युवाओं को दिया प्रशिक्षण।
- अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी, पानीपत और फरीदाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र संचालित।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

- 13 नये राजकीय व 125 नये निजी आईटीआई. शुरू।
- 18 राजकीय आई.टी.आई. के भवनों का निर्माण पूर्ण।
- राजकीय आई.टी.आई. में 18 नये व्यवसाय कोर्स शुरू, 1053 नई ट्रेड यूनिटें व 16,848 अतिरिक्त सीटें की।

जगमग हरियाणा

म्हारा गांव-जगमग गांव

- ग्रामीण घरेलू क्षेत्र के बकायों तथा हाई लाईन लॉसिज़ का हल निकाला।
- 237 फीडरों में लगभग 1256 गांव शामिल, जिनमें बिजली सप्लाई 24 घंटे बढ़ाई।
- 160 फीडरों में लगभग 656 गांव शामिल, जिनमें बिजली सप्लाई 15 घंटे बढ़ाई।
- 30 फीडरों में लगभग 81 गांव शामिल, जिनमें बिजली सप्लाई 18 घंटे बढ़ाई।
- पंचकूला, अम्बाला व गुरुग्राम जिलों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना

- ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 316 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- 33 नये के.वी. सब-स्टेशन, 11 के.वी. लाईनें, 11 के.वी. फीडरों की क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

बिजली आपूर्ति में ढांचागत सुधार

- 92 नये सब-स्टेशन स्थापित, 325 सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई।
- 5875 एम.वी.ए. की अतिरिक्त प्रसारण क्षमता तथा 940 किलोमीटर की प्रसारण लाईनें जोड़ी।
- 5665 किलोमीटर लम्बी लाईनें बिछाई, 55,936 नये ट्रांसफार्मर लगाए।
- वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 2688.83 करोड़ रुपये खर्च।

बिजली आपूर्ति में ढांचागत सुधार

- उजाला योजना के तहत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में 60-60 लाख LED बल्ब वितरित करने का लक्ष्य। अब तक लगभग एक करोड़ 28 लाख LED बल्ब, एक लाख 35 हजार LED ट्यूब तथा 36 हजार पंखे वितरित।
- एक नई योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण घरेलू फीडरों की कनैक्टिड ढाणियों के लिए चार्जिज उपभोक्ताओं से नहीं वसूले जा रहे हैं तथा प्रत्येक कृषि फीडर पर प्रोटोकॉल एडवांस टाइप (पी.ए.टी.) स्थापित किए जा रहे हैं।

बिजली बिल जुर्माना माफी योजना

- घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु शुरू।
- जनवरी, 2017 तक लगभग 1,79,521 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया।
- उपभोक्ताओं के लगभग 677 करोड़ रुपये के बिलों का निपटान।

आधुनिकता की मिसाल बनी एक्सप्रैस-वे एवं सड़कें

कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस-वे

- 2320 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित व दोबारा शुरू।
- 135.65 किलोमीटर लम्बे इस एक्सप्रैस-वे के 52.33 किलोमीटर मानेसर-पलवल खण्ड पर यातायात शुरू।
- 136 किलोमीटर लम्बे कुण्डली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रैस-वे निर्माणाधीन।

और जल्द ही दिल्ली के मुकरबा चौक से पानीपत तक 70 किलोमीटर का एन.एच.-1

राजमार्गों एवं सड़कों का कायाकल्प

- 5595 करोड़ रुपये की लागत से 12799 कि.मी. लम्बी सड़कों का सुधार।
- 595 कि. मी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार।
- वर्ष 2017-18 में 1625 करोड़ रुपये का कार्यक्रम तैयार।
- 530 कि.मी. लम्बे 5 नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित।

पुलों का निर्माण

- 14 आर.ओ.बी. (रेलवे ओवर ब्रिज) तथा 12 आर.यू.बी. (रेलवे अण्डर ब्रिज) के निर्माण पर 572 करोड़ रुपये खर्च।
- 25 आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी.का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- प्रदेश में 12 टोल टैक्स बैरियर हटाए गए।

एक्सप्रैस-वे एवं सड़कें

- 557 करोड़ रुपये की लागत से 151 भवनों का अभूतपूर्व विकास किया।
- हरियाणा राज्य सड़क विकास निगम द्वारा प्रदेश के एन.सी.आर. क्षेत्र में सड़क एवं पुलों के निर्माण पर 442 करोड़ रुपये खर्च।
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधारीकरण पर 3563 करोड़ रुपये खर्च।

हरियाणा की नई पहचान-मैट्रो, रेल एवं हवाई सेवाएं

रेल सेवाएं

- 81 कि.मी. सोनीपत-जीन्द रेलवे लाईन जनता को समर्पित।
- फरूखनगर-चरखी दादरी (वाया झज्जर) 72 कि.मी. लम्बी रेल लाईन की प्रक्रिया शुरू।
- हिसार-नरवाना के बीच 65 कि.मी. रेल लाईन का सर्वे शुरू।
- मथुरा-पलवल की चौथी लाईन 80 कि.मी., बाईपास अम्बाला-मोहड़ी-शम्भु 7 कि.मी. तथा रोहतक-भिवानी 48 कि.मी. की तीन नई रेल परियोजनाएं स्वीकृत।

शान की सवारी मैट्रो

- 13.87 कि.मी. लम्बी बदरपुर-मुजेसर मैट्रो शुरू।
- गुरुग्राम के हुडा सिटी सेन्टर से बावल तथा हुडा सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन, गुरुग्राम तक।
- सोनीपत के कुण्डली से नरेला, दिल्ली तक।
- फरीदाबाद के वाई.एम.सी.ए .चौक से बल्लभगढ़ तक।
- दिल्ली मैट्रो का बहादुरगढ़ तक विस्तार की योजना।
- गुरुग्राम-फरीदाबाद मैट्रो को जोड़ने की योजना।

हवाई सेवाएं

- हिसार एयरोड्रोम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में होगा विकसित।
- करनाल हवाई अड्डे को घरेलू हवाई अड्डा बनाया जायेगा।
- चण्डीगढ़ हवाई अड्डे का शुभारम्भ।

रेल सेवाएं

- पर्यावरण के संरक्षण के लिए देश की पहली सी.एन.जी. आधारित डी.ई.एम.यू. रेल सेवा रेवाड़ी से रोहतक के बीच शुरू।
- प्रदेश में रेल कोच फैक्टरी स्थापित की जा रही है।
- सेतु-भारतम योजना के तहत वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लाईन क्रॉसिंग मुक्त करने का लक्ष्य।

अंत्योदय दर्शन से गरीबों का कल्याण

'सामाजिक सम्मान भत्ता'

- 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं, दिव्यांगों, बौने एवं किन्नरों को 1600 रुपये मासिक पेंशन।
- पहली नवम्बर, 2017 से मिलेंगे 1800 रुपये।

'थारी पेंशन-थारे पास'

- हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत-प्रतिशत पेंशन लाभार्थियों के खाते में।
- सभी पेंशन बैंकों व डाकघरों के माध्यम से जमा।

गरीबों का कल्याण

- निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 700 रुपये की।
- जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे उन कश्मीरी परिवारों को 1000 रुपये प्रतिमास प्रति सदस्य की दर से (अधिकतम 5000 रुपये प्रति परिवार) 5 वर्ष तक वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो।
- 18 वर्ष की आयु तक स्कूल न जा सकने वाले निःशक्त बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमास की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्राथमिक ध्येय
सर्वजन हिताय

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

- सभी वर्ग की बी.पी.एल.विधवाओं को उनकी लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये।
- अनुसूचित, विमुक्त एवं टपरीवास जाति के बी.पी.एल. परिवारों को लड़की की शादी के लिए 41,000 रुपये।
- सभी वर्ग की विधवाओं/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाएं, अनाथ/ बेसहारा बच्चों की शादी के लिए 41,000 रुपये।
- सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित बीपीएल.परिवारों को लड़की की शादी के लिए 11,000 रुपये।
- समाज के सभी वर्गों, जिनके पास ढाई एकड़ कृषि भूमि या एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय है, को लड़की की शादी के लिए 11,000 रुपये।
- किसी भी जाति एवं आय वर्ग से सम्बन्धित महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31,000 रुपये।

डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना

- मैट्रिकोतर स्तर तक कक्षावार 8000 से12,000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति।
- पिछड़े वर्ग के दसवीं कक्षा के छात्रों को प्रतिशतता के आधार पर प्रोत्साहन राशि।

प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्तियां

- मैट्रिकोतर कक्षा के छात्रों को 230 रुपये से 1200 रुपये तक मासिक छात्रवृत्ति।
- पिछड़े वर्ग के छात्रों को 160 रुपये से 750 रुपये मासिक छात्रवृत्ति।
- सभी नॉन-रिफण्डेबल फीसों की प्रतिपूर्ति।

छात्रावास निर्माण

- अनुसूचित जाति की छात्राओं के छात्रावास निर्माण के लिए सरकारी संस्थाओं को 100 प्रतिशत राशि।
- गैर सरकारी संस्थाओं को छात्रावास बढ़ोतरी हेतु 90 प्रतिशत राशि।
- अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रावास निर्माण/बढ़ोतरी पर 45 प्रतिशत राशि भारत सरकार, 45 प्रतिशत राज्य सरकार व 10 प्रतिशत राशि सम्बन्धित संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा वहन।

गरीबों का कल्याण

- अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, लड़कियों को सिलाई का एक वर्षीय प्रशिक्षण। इस दौरान उन्हें कच्चा सामान खरीदने हेतु 300 रुपये एवं मासिक भत्ता 600 रुपये दिया जाता है।
- अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिए एक वर्ष का मुफ्त प्रशिक्षण हारट्रोन के माध्यम से दिया जाता है।

अन्य कल्याणकारी फैसले

- अनुसूचित जातियों के हितार्थ एवं सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु उच्च स्तरीय कमेटी गठित।
- अनुसूचित जाति, जनजाति व अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के तहत 85,000 से 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद।
- एससी.एवं बी.सी. वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं हेतु मुफ्त प्रशिक्षण।
- हरियाणा विमुक्त घुमन्तु जाति विकास बोर्ड गठित।
- गाडी-लोहार जाति टपरीवास जाति की सूची में शामिल।

पर्यटकों को लुभाता हरियाणा

स्वदेश दर्शन योजना

- कुरुक्षेत्र शहर के पांच प्रमुख स्थान शामिल।
- सन्निहित सरोवर, अमीन कुण्ड, नरकातारी, ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर एवं कुरुक्षेत्र शामिल।
- भारत सरकार द्वारा 97.34 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत।

धार्मिक स्थलों की यात्रा

- स्वर्ण जयन्ती गुरु दर्शन यात्रा योजना।
- प्रति वर्ष 50 व्यक्तियों को 6000 रुपये या वास्तविक खर्चे का 50 प्रतिशत प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता।
- स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री, अधिकतम 50 यात्रियों को वित्तीय सहायता।
- मानसरोवर यात्रा योजना के तहत 50,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री, अधिकतम 50 यात्रियों को वित्तीय सहायता।

पर्यटन को बढ़ावा

- हरियाणा केवल एक ऐसा राज्य जहां होटल प्रबन्धन से संबंधित पांच संस्थान कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर व फरीदाबाद में है।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा ट्रैवल गाइड' प्रकाशित।
- नारनौल-महेन्द्रगढ़-माधवगढ़-रेवाड़ी को ग्रामीण पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए 99.95 करोड़ रुपये के लागत की एक परियोजना।

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण

सरस्वती नदी का पुनरोद्धार

- सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड गठित।
- हरियाणा गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के प्रति जन जागरण हेतु सरस्वती महोत्सव आयोजित।
- मुगलावाली (यमुनानगर) में सरस्वती नदी की खुदाई शुरू, अन्तर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में होगा विकसित।

पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना

- राज्यस्तरीय संग्रहालय पंचकूला में होगा स्थापित।
- राखीगढ़ी (हिसार) में एक स्थल संग्रहालय व व्याख्यान केन्द्र की स्थापना।

कला एवं संस्कृति को बढ़ावा

- सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान-प्रदान के उद्देश्य से राज्य सरकार व भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, नई दिल्ली के बीच समझौता।
- लोक कलाओं एवं संस्कृति के संवर्द्धन के लिए खण्ड व जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित।
- गीता जयन्ती उत्सव कुरुक्षेत्र के साथ-साथ राज्य के सभी जिलों में आयोजित।
- 'एक भारत श्रेष्ठ-भारत' कार्यक्रम के तहत अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए तेलंगाना राज्य के साथ समझौता।

महिलाओं के स्वावलम्बन पर बल

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

- लिंगानुपात एवं महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्यक्रम।
- प्रदेश के सभी जिलों में लागू। (मेवात को छोड़कर)
- कार्यक्रम के लागू होने के बाद लिंगानुपात में सुधार।
- अगस्त, 2017 तक लिंगानुपात की दर बढ़कर 909 हुई।

आपकी बेटी -हमारी बेटी

- अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये।
- सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये।
- अब परिवार में जन्मी तीसरी बेटी को भी मिल रहा लाभ।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना

- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के साथ शुरू।
- बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खुलेगा खाता।
- इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर सर्वाधिक।

महिला पुलिस थानों की स्थापना

- सभी जिला मुख्यालयों पर एक महिला पुलिस थाना।
- उप-मण्डल स्तर पर महिला हैल्प डैस्क स्थापित।
- इनमें महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।
- बलात्कार के मामलों की जांच एक माह में व छेड़छाड़ तथा यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच 15 दिन में पूर्ण करने के आदेश जारी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- गरीब महिलाओं को गैस कनैक्शन हेतु 1600 रुपये की राशि।
- अनुसूचित जाति, जनजाति व बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता।
- अब तक 3,25,140 गैस कनैक्शन वितरित।

महिलाओं को सम्मान

- महिला दिवस पर इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार।
- कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार।
- बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार।
- लाईफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, विशिष्ट उपलब्धियों पर खेल पुरस्कार, सरकारी व सामाजिक सेवा पुरस्कार।
- लिंगानुपात में सुधार के लिए वर्ष 2015 में नारी शक्ति पुरस्कार 'कानगी देवी अवार्ड' मिला।

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी			
	राशि रुपये में		
कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
मैट्रिक में	8000	6000	4000
बारहवीं में	12,000	10,000	8,000
ग्रामीण महिला खेल प्रतियोगिता पुरस्कार			
	राशि रुपये में		
ब्लाक स्तर पर	2100	1100	750
जिला स्तर पर	4100	3100	2100
राज्य स्तर पर	11,000	8100	4100
सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार			
	राशि रुपये में		
सर्कल स्तर पर	2000	1200	800
ब्लॉक स्तर पर	4000	3000	2000

महिलाओं को अन्य सुविधाएं

- छात्राओं के लिए 131 महिला बस सेवा शुरू।
- महाविद्यालयों की छात्राओं को राज्य परिवहन की बसों में 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा।
- आशाओं का मासिक मानदेय 1000 रुपये।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क से छूट।
- सभी स्कूलों में लड़कियों के लिये अलग शौचालय।
- महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य पर लगाने की छूट।

महिलाओं को अन्य सुविधाएं

- राज्य पोषण मिशन गठित एवं हरियाणा कन्या कोष स्थापित।
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए करनाल, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार व नारनौल में 'वन स्टॉप' सैंटर सखी स्थापित।
- हसनपुर (सोनीपत) में 'नन्दघर' नाम से देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केन्द्र शुरू।
- ऑप्रेशन 'मुस्कान' के तहत 3840 गुमशुदा बच्चों को उनके संरक्षकों को सौंपा।

महिला पुलिस थाना दूरभाष नम्बर

जिला	थाना प्रभारी	मोबाईल नं.	डब्लयूपीएस. दूरभाष नं.
पंचकूला	इंस्पेक्टर सुनीता	8146630022	8146612772
अम्बाला	पी. एस. आई. सीमा	9729990165	(0171)-2551091
कुरुक्षेत्र	एस. आई. प्रवीन	7056700135	(01744)-221091, 7056700835
करनाल	एस. आई. पावना	8572881091	(0184)-2251091
पानीपत	इंस्पेक्टर कविता	7056731091	(0180)-2691091
सोनीपत	इंस्पेक्टर कविता	8053882349	(0130)-2241091
सोनीपत (खानपुर कलां)	एल./एस. आई. कमलेश	8053882350	(01263)-283100
रोहतक	इंस्पेक्टर गरिमा देवी	8199001091	(01262)-271091
झज्जर	इंस्पेक्टर सीमा	8930111091	(01251)-252061
रेवाड़ी	इंस्पेक्टर सरोज बाला	7056666133	(01274)-251722
गुरुग्राम	इंस्पेक्टर कैलाश	9212283922	(0124)-2218057
फरीदाबाद	इंस्पेक्टर सुशील	9582200061	(0129)-2261092
यमुनानगर	इंस्पेक्टर शीला	8818001307, 8683996541	(01732)-251002
नूंह	इंस्पेक्टर कमलेश देवी	8397991091	01267-271590 7027881091
पलवल	इंस्पेक्टर कमला देवी	8930511091	(01275)-241091
नारनौल	एस. आई. नीलम	7056601091	(01282)-251091
भिवानी	इंस्पेक्टर लक्ष्मी देवी	8814011409	(01664)-251091 9466531520
सिरसा	पी. एस. आई. सीमा सोढी	8813801091	(01666)- 231091
फतेहाबाद	इंस्पेक्टर अरूणा	8814011721	(01667)-230150, 231091
हिसार	इंस्पेक्टर सरोज बाला	8814031091	(01662)-271091
जीन्द	एस. आई. सन्तोष देवी	8813991091	01681-247091 8814011537
कैथल	इंस्पेक्टर निर्मला	9053052118	01746-234009 9053052218
चरखी दादरी	एल./एस. आई. उर्मिला	9728589202	9991216522

खण्ड स्तर महिला हैल्प डैस्क स्थापित

जिला	खण्ड स्तर
गुरुग्राम	मानेसर
फरीदाबाद	बल्लभगढ़
पंचकूला	कालका
अम्बाला	नारायणगढ़
करनाल	असंध
	इन्द्री
यमुनानगर	बिलासपुर
	जगाधरी
कुरुक्षेत्र	शाहबाद
कैथल	कलायत
	गुहला
हिसार	बरवाला
सिरसा	ऐलनाबाद
	डबवाली

जिला	खण्ड स्तर
भिवानी	सिवानी
	तोशाम
	लोहारू
	सदर दादरी
जीन्द	नरवाना
	सफीदों
फतेहाबाद	रतिया
रेवाड़ी	बावल
	कोसली
पलवल	होडल
	हथीन
नारनौल	कनीना
	महेन्द्रगढ़
मेवात	फिरोज़पुर

जिला	खण्ड स्तर
	झिरका
	टेरू
	पुन्हाना
रोहतक	महम
सोनीपत	गोहाणा
	गन्नौर
	खरखौदा
पानीपत	समालखां
झज्जर	बेरी
	सिटी बहादुरगढ़

श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा

श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 2.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी

वर्ग	रुपये (प्रतिमाह)
अकुशल श्रमिक	8280.20
अर्द्धकुशल 'ए'	8694.20
अर्द्धकुशल 'बी'	9128.91
कुशल श्रमिक 'ए'	9585.35
कुशल श्रमिक 'बी'	10064.62
उच्च कुशल श्रमिक	10567.85

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना

- आगजनी एवं भवन इत्यादि गिरने से मृत्यु या अपंगता होने पर वित्तीय सहायता।
- श्रमिक की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तथा अपंगता होने पर एक लाख रुपये।
- गैर अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिक शामिल।

पंजीकृत मजदूरों के लिए सुविधाएं

- अंत्योदय आहार योजना के तहत रियायती भोजनालय।
- पहचान-पत्र के स्थान पर 'स्मार्ट कार्ड' जारी करने का निर्णय।
- श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति सहायता दो बच्चों से बढ़ाकर तीन लड़कियों तक।
- छात्रवृत्ति योजना का लाभ तीन बच्चों से बढ़ाकर तीन लड़कियों व दो लड़कों तक।
- कन्यादान योजना का लाभ दो लड़कियों से बढ़ाकर तीन लड़कियों की शादी तक।
- कार्यस्थल से बाहर मृत्यु होने पर आश्रितों को 2 लाख रुपये की घोषणा।
- दिव्यांग होने पर सहायता राशि में वृद्धि की घोषणा।

श्रमिकों को आर्थिक सहायता

- भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली निःशक्तता पेंशन 3000 रुपये प्रतिमास करने की घोषणा।
- भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में अपंजीकृत मजदूर की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि।
- अंशदाता श्रमिकों के लिए एल.टी.सी., सिलाई मशीन, साइकिल देने की योजना के तहत वेतन सीमा 18 हजार रुपये करने की घोषणा।
- वेतन मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) 2016 पारित।
- हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों की बेटी की शादी हेतु कन्यादान राशि 11 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की घोषणा।

वीर एवं शहीदों का बढ़ाया सम्मान

अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी

- युद्ध में शहीद हुए सेना व अर्द्धसैनिक बल के जवानों को 50 लाख रुपये।
- आई.ई.डी. बलास्ट के दौरान शहीद होने पर 50 लाख रुपये।
- युद्ध/आतंकवाद तथा अन्य घटना में घायल हुए सैनिकों को निःशक्तता के आधार पर 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपये।
- युद्ध/आतंकवाद तथा अन्य घटना में घायल हुए अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को निःशक्तता के आधार पर 15 लाख, 25 लाख तथा 35 लाख रुपये।

वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी

- सेना में कमीशन पाने वाले अधिकारियों को कुशल प्रशिक्षण उपरांत एक लाख रुपये।
- द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा विधवाओं को 4,500 रुपये मासिक।
- भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को 3000 रुपये मासिक।
- 1962, 1965 व 1971 की युद्ध विधवाओं को 3000 रुपये मासिक तथा 400 रुपये प्रतिवर्ष वृद्धि।
- शहीद सैनिकों के 145 आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी।

अन्य सुविधाएं

- मातनहेल (झज्जर) में खोला जाएगा सैनिक स्कूल।
- दिव्यांग, नेत्रहीन, पैराप्लेजिक, टैटराप्लेजिक और हैमियाप्लेजिक भूतपूर्व सैनिकों को 3000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता तथा 400 रुपये प्रतिवर्ष वृद्धि।
- हरियाणा के पैराप्लेजिक पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों के लिए पैराप्लेजिक सैन्टर, मोहाली व किरकी (पूणे) की वित्तीय सहायता 85,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये प्रति सैनिक वार्षिक की।
- राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, देहरादून के छात्रों को 50,000 रुपये प्रति छात्र वार्षिक छात्रवृत्ति।
- सेना मेडल डिसटिंगविस्ड सर्विस/डिवोशन टू ड्यूटी के अवार्डी, जो कि फोर्सिज के हों और जिन्हें यह अवार्ड 31 मार्च, 2008 व 19 फरवरी, 2014 से पहले प्राप्त हुआ हो, को 34,000 रुपये नगद व 3,500 रुपये एन्यूटी दी जाती है तथा जिन्हें यह अवार्ड 19 फरवरी, 2014 के बाद मिला है, उन्हें 1.75 लाख रुपये की एकमुश्त नकद राशि।

हमारा प्रयास सबको आवास

दीनदयाल जन आवास योजना

- निम्न तथा मध्यम क्षमता के शहरों में सस्ती प्लॉटिड आवासीय कॉलोनी स्थापित करना।
- मध्यम संभावित शहरों में लाईसेंस शुल्क व बाहरी विकास शुल्क की दरें कम करना।
- अब तक 505 एकड़ भूमि के 55 लाईसेंस मंजूर।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- मिशन सभी के लिए घर-2022 के तहत शहरी गरीबों के आवासीय ऋणों पर ब्याज दरों में 6.5 प्रतिशत की छूट।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं कम आय श्रेणी के लोगों के लिए आवास सुविधा।
- नए मकान के निर्माण, मकान खरीद एवं वर्तमान मकान का नवीनीकरण शामिल।

कमजोर वर्गों के लिए आवास

- 11,259 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स के निर्माण की मंजूरी।
- पंचकूला में सैनिक व अर्धसैनिक बलों के लिए 342 टाईप 'ए' व 234 टाईप 'बी' फ्लैट्स निर्माणाधीन।
- विभिन्न वर्गों के लिए 15,968 फ्लैट्स निर्मित, जिनमें से 15,602 ई.डब्ल्यू.एस. मकान एवं बी.पी.एल. परिवारों तथा 366 अन्य वर्गों के लिए।

कर्मचारियों के कल्याणार्थ योजनाएं

कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

- सातवां वेतन आयोग लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।
- पहली जनवरी, 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करके उनके पूर्व संशोधित वेतनमान, जिस पर वे सेवानिवृत्त हुए थे, के अनुरूप पे-बैंड और ग्रेड-पे में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी।

अनुबंध कर्मचारियों को सुविधाएं

- वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि।
- सेवा अवधि के दौरान एडहॉक, अनुबंध व डी.सी. रेट पर लगे कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशि।
- एक्सग्रेसिया पॉलिसी के तहत गैस्ट टीचर्स की मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगी 3 लाख रुपये की आर्थिक वित्तीय सहायता ।

कर्मचारियों को आर्थिक मदद

- सभी सफाई कर्मचारियों के लिए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को दो जोड़ी वर्दी व एक जोड़ी जूता वार्षिक देने एवं सभी नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्ग का बैकलॉग पूरा करने की घोषणाएं।
- 972 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वर्ण जयंती मैडल।
- असामाजिक तत्वों के साथ मुठभेड़ में शहीद व गंभीर रूप से घायल होने पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि क्रमशः 10 लाख व 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख व 15 लाख रुपये की।
- 856 महिला एवं 5314 पुरुष पुलिस सिपाहियों की नियुक्ति, 5800 पुरुष व 1032 महिला सिपाहियों तथा 63 महिला एस.आई. की भर्ती प्रक्रियाधीन।

कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं

- पारिवारिक पेंशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- पारिवारिक पेंशन योजना के दायरे को बढ़ाया गया।
- निःशक्तता के कारण आजीविका से वंचित लड़की को उसकी शादी के बाद पारिवारिक पेंशन तथा सेवानिवृत्ति से पहले या उसके पश्चात पैदा हुए पात्र निःशक्त बच्चे को मिलेगा पेंशन का लाभ।
- दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों का मकान भत्ता 30 प्रतिशत।
- कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का होगा गठन।।

प्रदेश में हुआ उद्योगों का विस्तार

उद्यम प्रोत्साहन नीति

- राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 8 प्रतिशत से अधिक करना।
- चार लाख से अधिक लोगों को रोजगार देना।
- एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना।
- नीति के चार प्रमुख स्तम्भ **निर्बाध** (NIRBADH) (New Industrial Regulation by Automatic Approvals and Delegation in Haryana), **फाईन** (FINE) (Financial Incentives and No Enhancements) **विस्तार** (VISTAR) (Vat, Interest Stamp Duty, Audit Assistance and Rating) तथा **प्रणेता** (PRENTA) (Professional and New Entrepreneurs Tax Assistance)

भूमि परियोजनाओं की जल्द स्वीकृति

- 31 खण्डों में सी.एल.यू. और एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं।
- 75 खण्डों में सी.एल.यू. स्वतः होगा।
- 10 करोड़ रुपये से अधिक अनुमोदनों, स्वीकृतियों और एक एकड़ से अधिक की भूमि परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थित हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा।
- 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं तथा एक एकड़ से कम की भूमि परियोजनाओं की स्वीकृति जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा

- कुल 17,135 सूक्ष्म व लघु उद्योग तथा 447 मध्यम व बड़े उद्योग स्थापित हुए, जिनमें 24,793 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश हुआ तथा 2,48,052 लोगों को रोजगार मिला।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उद्यमकर्ता ज्ञापन फाइल करने की ऑनलाइन सुविधा।
- वर्तमान में 74 नई ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध।
- वर्ष 2015-16 में Ease of Doing Business की रैंकिंग में हरियाणा 14वें स्थान से छठे स्थान पर आया।

उद्योगों का विस्तार

- हरियाणा देश के कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत एक्सीलेटर, 52 प्रतिशत क्रेन्स, 50 प्रतिशत कारें और 33 प्रतिशत टू-व्हीलरस का योगदान देने वाला राज्य।
- वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदेश का निर्यात लगभग 81,220 करोड़ रुपये हुआ।
- अनुसूचित जाति के लोगों व महिलाओं को रोजगार देने पर प्रतिवर्ष 36 हजार रुपये तथा सामान्य श्रेणी के लोगों को रोजगार देने पर प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की रोजगार सृजन सब्सिडी पांच साल तक देने का प्रावधान।
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति तथा 'मेक इन इण्डिया' की पहलों के तहत राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सैकेण्डरी सेक्टर का योगदान 27 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत हुआ।
- थीम कलस्टर-पर्यटन, मनोरंजन, उद्योगों इत्यादि के लिए के.एम.पी. के साथ-साथ ग्लोबल इकॉनोकिम कॉरीडोर की स्थापना का निर्णय।

प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा

हैपनिंग हरियाणा-ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट

- सम्मिट में 12 देशों, चीन, चेक गणराज्य, जापान, मॉरीशस, मलावी, न्यूजीलैंड, पेरू, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ट्यूनीशिया, यू.के. और कनाडा के ओंटारियो प्रान्त हुए शामिल।
- कई देशों के राजदूतों, हाई कमिशनर्स सहित 3000 प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों और उद्यमियों ने भाग लिया।
- कुल 359 एम.ओ.यू. हुए, जिनसे लगभग 5.84 करोड़ रुपये के निवेश एवं 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना।
- 10 प्रतिशत एम.ओ.यू. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ।
- वर्ष 2018 में सम्मिट का होगा पुनः आयोजन।

विभिन्न क्षेत्रों में हुए 359 एम.ओ.यू.

क्षेत्र	एमओयू की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)	प्रस्तावित रोजगार
रक्षा एवं एयरोस्पेस	2	2170	10000
शिक्षा एवं कौशल विकास	11	976.25	3170
निर्माण क्षेत्र	112	822949	37718
रियल एस्टेट	23	105850.38	118502
आधारभूत संरचना	13	286925	122900
एग्रो खाद्य प्रसंस्करण तथा सम्बद्ध उद्योग	49	18457.48	21541
इलैक्ट्रोनिक, आई.टी., आई.टीज	37	9839.36	106805
फार्मास्यूटिकल एवं रसायन उद्योग	8	1822.54	1603
ऑटो, ऑटो कम्पोनेंट्स एण्ड लाईट इंजीनियरिंग	16	12675	7236
टैक्सटाईल/अपैरल/बुनाई-कढ़ाई/टैक्निकल टैक्सटाईल	17	463.89	6702
फुटवियर एण्ड एसैसरीज	9	241.73	1622
ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा तथा सोलर पार्क	41	122112.5	51705
निवेश प्रोत्साहन समर्थन	21	25926.5	12649
कुल	359	584282.62	502153

» एम.ओ.यू. को क्रियान्वित करने के लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने रिलेशनशिप मैनेजर किए नियुक्त।

हरियाणा अप्रवासी दिवस सम्मेलन

- गुरुग्राम में आयोजित इस सम्मेलन में हुए कुल 24 एम.ओ.यू.।
- राज्य में 20,430 करोड़ रुपये का निवेश एवं 45,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना।

विदेशी निवेश को बढ़ावा

- हरियाणा के एन.सी.आर. क्षेत्र से बाहर के जिलों में 1,65,568 करोड़ रुपये का उत्साहवर्धक निवेश हुआ, जिसके लिए कुल 146 एम.ओ.यू. हुए।
- वांडा ग्रुप ने डेढ़ से दो लाख रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु निवेश करने, झज्जर में समेकित औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने, पैनासोनिक द्वारा झज्जर टैक्नो पार्क में स्टोरेज बैटरी प्लांट स्थापित करने तथा मेदांता ने एक मैडिकल स्कूल और 1000 बिस्तरों का अस्पताल खोलने की घोषणा की।
- 9 फूड प्रोसैसिंग इकाइयां स्थापित तथा 17.28 करोड़ रुपये का अनुदान।
- बरही (सोनीपत) में 75 एकड़ क्षेत्र में 177 करोड़ रुपये के निवेश से मेगा फूड पार्क की स्थापना, जिससे 12 हजार व्यक्तियों के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

विदेशी दौरों से बढ़ा निवेश

- अमेरिका व कनाड़ा दौरे के दौरान हुए पांच समझौते।
- यूनाइटेड टैक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (United Technologies Corporation), एलगोनक्वीन कॉलेज (Algonquin College), अप्लाईड मैटीरियल (Applied Material), गूगल (Google) (डिजिटल साक्षरता हेतु) तथा सिस्को (CISCO)।
- 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश व 40 हजार लोगों को रोजगार की सम्भावना।
- चीन व जापान दौरे के दौरान हुए 8 समझौते।
- जापान के मिजुहों बैक लिमिटेड के साथ समझौता।
- वाण्डा, चाईना लैंड डैवलेपमैंट कम्पनी, जैड.टी.ई. कॉरपोरेशन इत्यादि बड़ी कम्पनियों के साथ समझौता।

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के नए प्रयास

महिला सुरक्षा प्रबन्ध

- हर जिला मुख्यालय पर एक पुलिस थाना तथा उपमण्डल स्तर पर महिला हैल्प डैस्क स्थापित।
- इनमें महिला पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति।
- बलात्कार के मामलों की जांच एक महीने में पूरी करने के आदेश।
- छेड़छाड़ तथा यौन उत्पीड़न के मामलों में 15 दिन के अन्दर जांच पूरी करने के आदेश।

सुरक्षा एजेंसियों का आधुनिकीकरण

- सिटीजन पोर्टल 'हरसमय' 24 घण्टे उपलब्ध।
- अब घर से ही करवा सकेंगे शिकायत दर्ज।
- एनआरआई.की शिकायतों के निपटान हेतु विभाग की वैब साईट पर एन.आर.आई. सैल शुरू।
- आप्रेशन 'संजय' के तहत गुरुग्राम तथा एन.एच.-1 पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगेंगे।

अन्य सुधार

- ''पुलिस भर्ती में पारदर्शिता'' (टी.आर.पी.) पद्धति लागू।
- हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण अधिनियम 'हरकोका' शीघ्र होगा लागू।
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु सड़क सुरक्षा निधि।
- भौंडसी, सुनारिया, हिसार और पंचकूला में 4 न्यायवैधिक प्रयोगशालाएं होंगी स्थापित।
- विभाग द्वारा 14 पुलिस पब्लिक स्कूल चलाए जा रहे हैं।

सुदृढ़ अर्थव्यवस्था विकास का परिचायक

मजबूत वित्त प्रबन्धन

- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों पर 8.7 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित।
- वर्ष 2016-17 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1,80,174 रुपये अनुमानित, जबकि वर्ष 2015-16 में 1,62,034 रुपये थी।
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक आंकलन हेतु श्वेत पत्र जारी।
- वर्ष 2017-18 में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1,02,32939 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान।

'कैशलेस' बनता हरियाणा

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बन्द करने के निर्णय को प्रदेशवासियों ने तहेदिल से स्वीकारा।
- लोगों को कैशलेस मोड अपनाने के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- डेबिट कार्ड, क्रैडिट कार्ड, पी.ओ.एस., यू.पी.आई., ई-वॉलेट, यू.एस.एस.डी. व आधार आदि से लेन-देन शुरू।
- लोगों द्वारा उपरोक्त सुविधाओं का उपयोग करने पर उनके खाते में 5 रुपये की प्रोत्साहन राशि जमा।
- 'भीम एप' के माध्यम से अंगूठा लगा कर कैशलेस लेन-देन जारी।
- योजना के तहत ईनाम स्वरूप पुरस्कार 1000 रुपये के 50, पांच हजार रुपये के 10 तथा दस हजार रुपये के 5 पुरस्कार।
- कैशलेस लेन-देन बारे जिला मुख्यालय, उप-मण्डल, तहसील व उप-तहसील स्तर पर पी.ओ.एस. मशीनें लगाई जा रही हैं।
- कैशलेस लेन-देन बारे जागरुकता लाने हेतु विभिन्न जिलों में 'डिजीधन' मेलों का आयोजन।

पत्रकारों को अपार सुविधाएं

अनेक घोषणाएं

- 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन।
- 20 वर्ष तक किसी एक संस्थान में काम करने की शर्त समाप्त।
- सभी मीडियाकर्मियों को जीवन बीमा योजना का लाभ।
- 5 लाख रुपये तक की नई कैशलेस मेडिक्लेम योजना।
- 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि के भुगतान पर 10 व 20 लाख रुपये तक का जीवन बीमा।
- उपमण्डल स्तर पर भी इलैक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को मान्यता।
- वैबपोर्टल व सोशल मीडिया पर एक्टिव पत्रकारों को भी मान्यता।

आधुनिक एवं सुगम परिवहन सेवाएं

बस सुविधाओं में विस्तार

- वरिष्ठ नागरिकों (महिला/पुरुष) को राज्य के भीतर व बाहर तक के किरायों में 50 प्रतिशत छूट।
- वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को राज्य परिवहन की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा।
- आपातकाल के पीड़ित पति/पत्नी को सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा एवं वोल्वों बसों के किराये में 75 प्रतिशत की छूट।

सुरक्षित परिवहन

- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति की तर्ज पर नई राज्य सड़क सुरक्षा नीति-2016।
- शहरी बस सेवाओं में तथा बड़े बस अड्डों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे।
- प्रथम चरण में 400 बसों में जी.पी.एस. प्रणाली लागू व शेष बसों में भी जल्द शुरू।

बस बेड़ों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार

- बस बेड़े में 484 नई बसें शामिल।
- 717 नई बसें शामिल करने की स्वीकृति।
- कालूवास (भिवानी) में चौथा चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है।
- कनहेली (रोहतक) में निरीक्षण और परीक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।
- छपेड़ा (मेवात) और बहीन (पलवल) में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

हर जन हो स्वस्थ

मिशन इन्द्रधनुष

- एक साल से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सम्पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य।
- चार चरणों में 2,62,024 गर्भवती महिलाओं एवं 9,61,785 बच्चों का टीकाकरण।
- हरियाणा देश के चार राज्यों में शामिल जहां टीकाकरण के तहत रोटा वायरस वैक्सिन की शुरुआत निःशुल्क।
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत दस टीका रोधक बिमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण।

मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना

- सरकारी अस्पतालों में द्वितीय स्तरीय सर्जरियां निःशुल्क।
- 73 मूलभूत प्रयोगशला जांच, एक्स-रे, अलट्रासाउंड, ई.सी.जी. निःशुल्क।
- 21 विभिन्न प्रकार की दंत चिकित्सा प्रक्रियों के साथ 213 विभिन्न आप्रेशन।
- रेफरल परिवहन इन्डोर उपचार सेवाएं निःशुल्क।

सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं

- 357 दवाईयां मुफ्त, 209 मैडिकल कंज्यूमेबलस (उपभोग्य), 36 लीलन आईटम्ज, 51 प्रोग्राम दवाईयां तथा 33 दंत सामग्री की सुविधाएं मुफ्त।
- पंचकूला, फरीदाबाद, भिवानी के अस्पतालों व खानपुर, पीज़ीआई, रोहतक, मेवात मेडिकल कॉलेज में एमआरआई. और सिटी स्कैन की सुविधा।
- पंचकूला, फरीदाबाद, अम्बाला कैंट व गुरुग्राम में कैथ लैब स्थापित।
- सभी जिला अस्पतालों में डेंगू निदान हेतु मुफ्त उपचार।
- पंचकूला, फरीदाबाद, अम्बाला कैंट, गुरुग्राम, सिरसा, हिसार व जींद में हिमोडायलिसिस की सुविधा शुरू।
- भिवानी व पंचकूला को 300 बिस्तरों का अस्पताल बनाया।

चिकित्सा शिक्षा का प्रसार

- कुटैल (करनाल) में मेडिकल विश्वविद्यालय।
- पंचकूला, भिवानी, जींद में सरकारी मेडिकल कॉलेज।
- बाढ़सा (झज्जर) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनेगा।
- पी.ज़ी.आई, रोहतक में वायरल डायग्नोस्टिक लैबोरेट्री।
- शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ में टी.बी. के प्रति मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का पता लगाने हेतु एक सी.बी.एन.ए.ए.टी. मशीन स्थापित।
- भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां में डायलिसिस मशीन और केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना।

बीमाकृत व परिवारों को ई.एस.आई. में स्वास्थ्य सुविधाएं

- ई.एस.आई. योजना सभी जिलों में लागू।
- शाहबाद व चरखी दादरी में चिकित्सा बीमा व्यवसायी प्रणाली।
- पानीपत व झाड़ली (झज्जर) में नई डिस्पेंसरी खुलेंगी।
- बरवाला (पंचकूला), साहा (अम्बाला) व खरखौदा (सोनीपत) में मोबाईल डिस्पेंसरी खुलेंगी।
- महेन्द्रगढ़ में नई ई.एस आई. डिस्पेंसरियां खुलेंगी।
- पंचकूला व रेवाड़ी ई.एस.आई. डिस्पेंसरी को किया अपग्रेड।

चिकित्सा क्षेत्र में कई सुधार

- 10 अस्पतालों, 14 सी.एच.सी., 20 पी.एच.सी. भवनों, 6 अस्पतालों, 14 सी.एच.सी. व 5 पी.एच.सी. को किया अपग्रेड।
- 389 नये डाक्टर भर्ती किये, 662 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण।
- सभी जिला नागरिक अस्पतालों में ई-उपचार प्रबन्धन तथा सूचना प्रणाली शुरू, जिसमें रोगी पंजीकरण, इलैक्ट्रोनिक स्वास्थ्य रिकार्ड और अन्य सहायक इकाइयां शामिल।
- तम्बाकू सामग्री युक्त गुटका और पान-मसाला पर प्रतिबन्ध।
- आधार सक्षम ऑनलाइन जन्म व मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के तहत जन्म से 5 साल तक के बच्चों का आधार सक्षम पंजीकरण किया जा रहा है।
- हरियाणा देश का पहला राज्य जहां परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों में गर्भनिरोधक टीका सर्वप्रथम शामिल।
- मोरनी व पिंजौर (पंचकूला) के पर्वतीय क्षेत्रों के दूर-दराज स्थानों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मोटर साइकिल एम्बुलैंस आरोग्य सेवा शुरू।
- ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों तथा अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ का वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाकर किया 1150 रुपये मासिक।

आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी

आयुष संस्थान

- पंचकूला में एम्स की तर्ज पर ऑल इण्डिया इंस्टीच्यूट फॉर आयुर्वेदा होगा स्थापित।
- श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, कुरुक्षेत्र में नई राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी एवं ड्रग टैस्टिंग लैबोरेटरी स्थापित।
- गांव पट्टीकड़ा (नारनौल) में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल जल्द।
- जिला स्तर पर 21 पंचकर्मा केन्द्र होंगे स्थापित।

आयुर्वेद को बढ़ावा

- 21 जून को हर वर्ष जिला व ब्लॉक स्तर पर योग दिवस का आयोजन।
- 6500 गांवों व कस्बों में योगशालाएं स्थापित करने का निर्णय, इस वर्ष 1050 योगशालाएं होंगी स्थापित।
- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष प्रकोष्ठ बनेंगे।
- कई जिलों में पंचकर्मा केन्द्रों पर पंचकर्मा की सुविधा उपलब्ध।

खेलों में हरियाणा का परचम

अभूतपूर्व खेल प्रतिभाएं

- रियो पैरा ओलम्पिक-2016 में साक्षी मलिक को कुश्ती में मिला कांस्य पदक।
- रियो पैरालिम्पिक-2016 में दीपा मलिक को शॉट पुट में रजत पदक।
- इन खेलों में प्रदेश के 29 खिलाड़ियों ने लिया भाग।

खिलाड़ियों को राष्ट्रीय सम्मान

- रियो ओलम्पिक-2016 में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
- हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, कुश्ती खिलाड़ी विनेश फौगाट, अमित कुमार व विरेन्द्र सिंह को अर्जुन पुरस्कार।
- कोच महावीर सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार।

खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार

- रियो पैरा ओलम्पिक-2016 में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को 2.50 करोड़ रुपये।
- रियो पैरालिम्पिक-2016 में रजत पदक विजेता दीपा मलिक को 4 करोड़ रुपये।
- इन खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 15-15 लाख रुपये।

भारत केसरी दंगल

- गुरुग्राम में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस पर आयोजित।
- प्रथम विजेता को एक करोड़ रुपये।
- दूसरे विजेता को 50 लाख रुपये।
- तीसरे विजेता को 25 लाख रुपये।

खेल संस्थानों की स्थापना

- खेल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना।
- पंचकूला में स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशनल कॉम्पलेक्स निर्माणाधीन।
- प्रत्येक जिले में स्वर्ण जयंती युवा विकास केन्द्र बनेंगे।
- स्वर्ण जयंती सैंटर ऑफ एक्सीलैंस बनेगा।
- कुल 440 गोल्डन जुबली खेल नर्सरियां खोली गईं।

अवार्ड

- खेल एवं शारीरिक उपयुक्तता नीति-2015 में भीम अवार्ड की भांति एकलव्य अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, रानी लक्ष्मी बाई अवार्ड, विक्रम आदित्य अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, अवार्ड फॉर शारीरिक शिक्षा अध्यापक पी.टी आई. एवं डी.पी.ई. दिए जाने का प्रावधान।

खेलों की पुरस्कार राशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी

खेल प्रतियोगिताएं	स्वर्ण पदक विजेता (रुपयों में)	रजत पदक विजेता (रुपयों में)	कांस्य पदक विजेता (रुपयों में)	प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी (रुपयों में)
ओलम्पिक में	6 करोड़	4 करोड़	2.50 करोड़	15 लाख
एशियन में	3 करोड़	1.50 करोड़	75 लाख	7.50 लाख
कॉमनवेल्थ गेम्स में	1.50 करोड़	75 लाख	50 लाख	7.50 लाख
राष्ट्रीय खेलों में	5 लाख	3 लाख	2 लाख	-
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में	3 लाख	2 लाख	एक लाख	-
राज्य स्तरीय अखाड़ा कुश्ती प्रतियोगिता	5,100	3,100	2,100	-
राज्य स्तरीय कुमार दंगल प्रतियोगिता	51,000	31,000	21,000	-
राज्य स्तरीय केसरी दंगल प्रतियोगिता	1.51 लाख	एक लाख	51,000	-

दीनदयाल उपाध्याय कबड्डी टूर्नामेंट

- राई (सोनीपत) में फरवरी, 2017 में आयोजित।
- प्रथम विजेता को एक करोड़ रुपये।
- दूसरे विजेता को 50 लाख रुपये।
- तीसरे विजेता को 25 लाख रुपये।

स्वर्ण जयन्ती खेल महाकुम्भ

- प्रदेश भर से लगभग पांच लाख खिलाड़ियों ने प्रतिभागिता हेतु करवाया पंजीकरण।
- विभिन्न 22 प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- जिला स्तर पर खिलाड़ियों को 100 रुपये प्रतिदिन।
- जिला स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने पर क्रमशः 2000, 1500 व 1000 रुपये तथा टीम प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने पर क्रमशः 1500, 1000 व 750 रुपये नकद ईनाम।
- राज्य स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने पर क्रमशः 5000, 3000 व 2000 रुपये तथा टीम प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने पर क्रमशः 3000, 2000 व 1000 रुपये नकद ईनाम ।

लगभग 12.29 करोड़ रुपये की राशि खिलाड़ियों को ईनाम स्वरूप वितरित

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सोलर पावर प्लांट क्षमता में बढ़ोतरी

- पानीपत में 10 मैगावाट तथा मिठठी (भिवानी) में 5 मैगावाट के सोलर पावर प्रौजेक्ट स्थापित।
- 37 मैगावाट धरातल आधारित तथा 57 मैगावाट रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित।
- गुरुग्राम में 121 देशों के संगठन के इन्टरनेशनल सोलर एलाएंस का वैश्विक सचिवालय निर्माणाधीन।
- विभिन्न जिलों में 441.6 लाख रुपये की लागत से 69 ऑफ ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित।

हरियाणा ग्लोबल सम्मिट

- हरियाणा सौर ऊर्जा नीति बनी।
- 44 निवेशकों ने 96,213 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति दी।

अक्षय ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा

- करनाल व पलवल में 4.20 मैगावाट क्षमता की दो परियोजनाएं स्थापित।
- सोनीपत में गैसीफायर तकनीक से 1000 किलोवाट तापीय ऊर्जा का संयंत्र स्थापित।
- सरकारी व अर्ध सरकारी क्षेत्रों में नए सोडियम वाष्प लैंप की खरीद पर प्रतिबन्ध।
- सरकारी एवं गैर सरकारी उपभोक्ताओं हेतु एल.ई.डी., लैंप, ट्यूब लाईट तथा ऊर्जा कुशल लाईटों का उपयोग अनिवार्य।
- विभिन्न श्रेणियों की व्यावसायिक ईमारतों में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ई.सी.बी.सी.) अनिवार्य।
- कुछ श्रेणियों हेतु सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य।

मनोहर ज्योति परियोजना

- 1,00,000 सौर प्रकाश प्रणालियां स्थापित।
- प्रथम चरण में 50,000 होंगी स्थापित।
- 225.12 लाख रुपये की लागत से कुल 5682 तथा 115 लाख रुपये की लागत से (2300 एल.ई.डी.) सौर घरेलू प्रकाश प्रणालियां स्थापित।

अवार्ड

- नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों की स्थापना के लिए एस.एन.ए.एस. की हरित भवनों की श्रेणी में राज्य तृतीय पुरस्कार से सम्मानित।

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन

सुशासित प्रशासन

- बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' का लक्ष्य।
- पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बड़ी खनन इकाइयों/ब्लॉकों के ठेके देने की बजाय छोटी खनन इकाइयों/ब्लॉकों के रूप में ठेके पर दिये जाने का महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय।
- जिससे छोटे उद्यमीयों का खनन में प्रवेश तथा कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार भी समाप्त।

सी.एम. विंडो स्थापित

- www.haryanacmoffice.gov.in सी.एम.वेबपोर्टल शुरू।
- हर जिला मुख्यालय तथा ब्लॉक स्तर पर स्थापित।
- 3 लाख 53 हजार 175 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें 2 लाख 98 हजार 14 शिकायतों का समाधान हुआ।

रोजगार से आत्मनिर्भर होते युवा

बेरोजगारी भत्ता योजना

- बैंकों के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता त्रैमासिक आधार पर।
- 1847 प्रार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में समायोजित करवाया।
- 80.76 करोड़ रुपये की राशि बेरोजगारी भत्तों के रूप में वितरित।
- बेरोजगारी भत्ता योजना की राशि में 12वीं या इसके समकक्ष, स्नातक और इसके समकक्ष व स्नातकोत्तर बेरोजगारों की राशि को किया क्रमशः 900, 1500 तथा 3000 रुपये मासिक।

सक्षम युवा योजना

- स्नातकोत्तर बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू।
- पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 3000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता एवं 100 घण्टे कार्य करने के एवज में 6000 रुपये प्रतिमाह मानदेय।

सक्षम युवा योजना

- 41,169 युवा पंजीकृत, जिनमें से 20,745 युवाओं को विभिन्न विभागों में कार्य उपलब्ध करवाया।
- अब तक मानदेय व बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुल 51.74 करोड़ रुपये वितरित।
- विभागीय वैबसाईट www.hreyahs.gov.in पर पंजीकरण।
- इसमें विज्ञान, गणित स्नातक तथा बीक़ॉम प्रार्थियों को किया शामिल।
- इसके अन्तर्गत 12वीं पास योग्य युवाओं को क्रमबद्ध अनुसार 100 घण्टे प्रतिमाह दिया जाएगा कार्य व मानदेय।
- हिसार में पायलट परियोजना के रूप में एक राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र स्थापित।

राजस्व बढ़ोतरी की दर सही दिशा में

ई-सेवाओं से हुए कार्य आसान

- कराधान के क्षेत्र में ई-पंजीकरण, कर की ई-अदायगी एवं रिटर्न की ई-फायलिंग, ई-निविदा एवं सी-फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू।
- शराब के अवैध व्यापार पर रोक लगाने हेतु आबकारी लाइसेंसदारियों के लिए ई-परमिट एवं ई-पास प्रणाली।
- ई-सेवाओं को लागू करके इंस्पैक्टर राज की दखलअदांजी को किया समाप्त।
- पहली बार व्यापारियों के लिए ई-रिफंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू।

करों में राहत

- जूता उद्योग को बढ़ावा देने हेतु 500 रुपये और इससे अधिक के एमआरपी. वाले जूतों पर कर की दर घटाकर 5 प्रतिशत करने और जूतों के ऊपर के हिस्से को वैट से छूट।
- कृषि आधारित उद्योगों पर राज्य में निर्मित 'खल', 'बिनौला', 'बेसन' तथा 'सूती धागा' कर मुक्त।

करों में राहत

- कृषि उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 'सेवियां' पर कर की दर घटाकर की 5 प्रतिशत।
- इलैक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री पर कर की दर घटाकर की 5 प्रतिशत।
- रसोई में पत्तेदार सब्जियों को काटने वाला 'छोटा टोका' कर मुक्त।
- एल.इ.डी. लाईटों, पाइप फिटिंग एवं प्री.फेब स्टील स्ट्रक्चर पर वैट की दर घटाकर की 5 प्रतिशत।
- मेहंदी पर वैट की दर घटाकर की शून्य।
- बायो डीजल पर लगने वाले 12.5 प्रतिशत वैट को किया समाप्त।
- ग्राहकों को खरीदे गए माल का बिल या invoice लेने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार 'अपना बिल अपना विकास' पुरस्कार योजना शुरू।
- जी.एस.टी. अधिनियम सफलतापूर्वक लागू।
- व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना।

डिजिटल हरियाणा की नई तस्वीर

सेवा का अधिकार अधिनियम-2014

- 273 सेवाएं अधिसूचित।
- 1000 रुपये से अधिक की सभी अदायगियां इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से।

जन्म पंजीकरण

- आधार कार्ड बनाने का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 375 स्थाई नामांकन केन्द्र स्थापित।
- अब तक 99.38 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

स्टेट पोर्टल-2015

- सभी विभागों/बोर्डों की वैबसाईट से जोड़ा।
- 135 ई-दिशा केन्द्रों तथा 4979 अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से 281 ई-सर्विसेज सेवाएं शुरू।
- अब तक 9984 सांझा सेवा केन्द्र स्थापित, 4979 केन्द्रों में सेवाएं शुरू।

पारदर्शी हरियाणा की नई पहचान

- भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने हेतु टोल फ्री चौकसी हेल्पलाइन नम्बर 1064 तथा टोल फ्री नम्बर 1800-180-2022।
- राज्य सतर्कता ब्यूरो ने जन साधारण को शिकायतें भेजने के लिए Whatsapp Number 9417891064 करवाया उपलब्ध।
- सभी विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त।
- भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरैंस की नीति पर अटल सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने के लिए विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 424 आपराधिक मुकदमे दर्ज किये।
- राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा 305 नई जाचें दर्ज। जिनमें से पंचकूला कौशल्या बांध घोटाला, पंचकूला शामलात जमीन का घोटाला, पंचकूला औद्योगिक प्लॉट आबंटन घोटाला, पिल्लर बॉक्स घोटाला, पांच सितारा पुल मैन होटल को रास्ता देने का घोटाला, एच.सी.एस. की नियुक्ति में अनियमितताएं, अम्बाला का मनरेगा घोटाला व एन.आई.टी.फरीदाबाद में 8012 वर्ग गज सरकारी जमीन घोटालों की जांच शामिल।

देसां में देस हरियाणा

- विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला हरियाणा अग्रणी राज्य।
- पहली बार सड़क निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी अपनाई।
- हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत-प्रतिशत पेंशन लाभार्थियों के खाते में।
- पर्यावरण के संरक्षण हेतु देश की पहली सी.एन.जी. आधारित डी.ई.एम.यू. रेल सेवा, रेवाड़ी से रोहतक के बीच शुरू।
- कुरुक्षेत्र में उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान।
- पहली बार व्यापारियों के लिए ई-रिफंड की ऑनलाइन सुविधा।
- सहकारी चीनी मिलों द्वारा कुल 3 करोड़ 62 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई, जोकि हरियाणा के इतिहास में सर्वाधिक।
- गन्ने की किस्मों में महत्वपूर्ण सुधार, जोकि 20 प्रतिशत बढ़कर 79 प्रतिशत, जो अब तक का सर्वाधिक प्रतिशत।
- हरियाणा देश का पहला राज्य, जहां देसी गाय का पास्चुरीकृत 'ए-2' दूध वीटा बूथों पर उपलब्ध।
- राज्य में पहली बार देसी गायों की सौन्दर्य प्रतियोगिता गांव बहुअकबरपुर (रोहतक) में।
- बारिश व नदियों के पानी के बहाव की निगरानी हेतु पहली बार व्हाटसअप जैसे सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल।
- कैथल में राजस्व रिकार्ड को संरक्षित रखने हेतु पहला आधुनिक राजस्व अभिलेखागार।
- समस्त हरियाणा अप्रैल, 2017 से कैरोसिन मुक्त हुआ।
- पंचकूला भारत का पहला जिला जिसने पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु मोटर साइकिल एम्बुलैंस आरोग्य सेवा शुरू की।
- स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में करनाल उत्तरी भारत में 2 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में प्रथम स्थान पर।
- गीता जयन्ती उत्सव पहली बार कुरुक्षेत्र की बजाय राज्य के सभी जिलों में आयोजित।
- पहली बार सभी पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश।
- सातवें वेतन आयोग को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।
- हरियाणा देश का पहला राज्य, जिसने परिवार नियोजन के साधनों में गर्भनिरोधक टीका सर्वप्रथम शामिल।
- हरियाणा केवल एक ऐसा राज्य जहां होटल प्रबन्धन से संबंधित पांच संस्थान कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर व फरीदाबाद में कार्यरत।
- हसनपुर एवं दनचौली माइनरों में 39 वर्ष बाद पहली बार पहुंचा नहरी पानी।
- माधोगढ़ व सुरहेति माइनरों (नारनौल-रेवाड़ी क्षेत्र) में 39 वर्ष बाद पहुंचा पानी।
- निंबेहड़ा माइनर (लोहारू क्षेत्र) में 30 वर्ष बाद पहुंचा पानी।
- दिवाना माइनर (नारनौल-रेवाड़ी क्षेत्र) में 24 वर्ष बाद पहुंचा पानी।
- प्रदेश की सबसे लम्बी नहर सोरा माइनर (लोहारू क्षेत्र) में तथा लाडावास, दमकोरा व डागरोली माइनरों (लोहारू क्षेत्र) में 20 वर्ष बाद पहुंचा पानी।

स्वर्ण जयन्ती वर्ष के दौरान आयोजित हुए कार्यक्रम

सांस्कृतिक कार्यक्रम

- जिला कुरुक्षेत्र में गीता जयन्ती समारोह के उपलक्ष्य में हरियाणा स्वर्ण जयन्ती उत्सव का आयोजन, जिसमें सात दिवसीय संगीत एवं नृत्य कार्यशाला आयोजित।
- कठपुतली शो का आयोजन, जिसमें महाभारत से सम्बन्धित श्रीमद्भगवद्गीता का पवित्र संदेश दिया गया।
- मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर, कुरुक्षेत्र में लुप्त हो रही मूर्ति कला को जीवंत रखने हेतु मूर्ति कला शिविर का आयोजन।
- चित्रकला प्रदर्शनी तथा मास्क मेकिंग का आयोजन, जिसमें कलाकारों ने अपनी-अपनी कला के रंग बिखेरे।
- उकलाना (हिसार) में सात दिवसीय नाट्य उत्सव का आयोजन।
- भिवानी में चिल्ड्रन लिट्रेचर फैस्टिवल-2017 का आयोजन।
- पंचकूला में स्वर्ण जयन्ती पत्रकार सम्मेलन में वीर एवं हास्य रस कवि सम्मेलन एवं नाट्यों की प्रस्तुति।
- टैगोर थियेटर, चण्डीगढ़ में त्रिभाषीय मुशायरा आयोजित।
- फरवरी, 2017 में भारत मुनि ऑडिटोरियम में इटली के कलाकारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन।
- भारत रंग महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के 6500 गांवों में सात दिवसीय अभिनय कार्यशाला का आयोजन।
- तीन दिवसीय हरियाणा रंग महोत्सव फरवरी, 2017 आयोजित।
- इसके अतिरिक्त लोगों को कला व संस्कृति से जोड़ने के लिए अलग-अलग जिलों यमुनानगर, जीन्द, अम्बाला, हिसार में राष्ट्रीय नाट्य एवं लोक कला महोत्सव आयोजित।
- रोहतक में महिला सशक्तिकरण को समर्पित Wow Womaina-संगीतमय शो का आयोजन।
- लोक नृत्य, लोक गीत एवं शास्त्रीय गायन के प्रति लोगों में रुचि बढ़ाने हेतु रोहतक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन।

निदेशक - सूचना ,जन संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्धारा प्रकाशित तथा संवाद सोसाइटी के माध्यम से मुद्रित (अक्तूबर - 2017)